the country. Establishment of new management colleges and institutes is approved by the AICTE subject to the academic and financial viability of the institutes to conduct the management education courses and fulfilment of the minimum norms and standards as prescribed by the AICTE. The AICTE while considering new proposal also keeps in view the requirement of managerial manpower in the country.

Denial of Budgetary support for revamping IISCO

655. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government has denied budgetary support for revamping IISCO;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the reasons for IISCO facing modernisation problems despite its existing infrastructure and related facilities;

(d) whether any alternatives of phased rehabilitation or modernisation of IISCO have been drawn up, entailing lower initial investment and subsequent phased investments through internal accruals and/or by raising commercial borrowings; and

(e) if so, details thereof and if not, the reasons therefor in the light of the fact that private sector iron and steel plants with lower capacities and lower investments are reported to be viable?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) and (b) Due to resource constraint it has not been possible for the Government to provide budgetary support for modernisation of IISCO.

(c) to (e) Since Indian Iron & Steel Company Limited (IISCO) became a sick industrial company in terms of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (as amended in February, 1994) a reference was made by the Board of Directors of IISCO to BIFR on 22nd June, 1994, as required under Section 15 of the Act, for determination of measures to be adopted with respect to the company.

Any scheme to be taken up for modernisation of IISCO will, therefore, have to be in accordance with the orders of the BIFR in this regard.

उर्वरकों के धारण मूल्य तथा बिक्री मूल्य में अन्तर

656. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्वरकों के धारण मूल्य तथा बिक्री मूल्य में अन्तर काफी बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्तर में इस वृद्धि का अर्थ व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कोई सुझाव दिये हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो) (क) से (ग) इस समय यूरिया ही केवल एक उर्वरक है, जो सांविधिक मूल्य आवंटन और संचलन नियंत्रण के अन्तर्गत आता है। अतः इसलिए निर्धारण मूल्य व राज सहायता योजना केवल यूरिया पर लागू है। निर्धारण मूल्य (अर्थात् उत्पादन लागत जमा अलग-अलग एककों के लिए सरकार द्वारा यथा मूल्यांकित शुद्ध लागत पर लाभ) तथा सांविधिक रूप से अधिसूचित बिक्री मूल्य के बीच का अन्तर राज सहायता के रूप में सरकार द्वारा दिया जाता है। जबकि अलग-अलग संयंत्रों के मामले में इस अन्तर में कमी के उदाहरण है, इसलिए समग्र आधार पर इस अन्तर में बढ़ी हुई उत्पादन लागत तथा किसानों को बिक्री मूल्य में इन वृद्धियों की पूरे गैर-समंजन के कारण वृद्धि हो रही है।

25.8.1992 से सभी फास्फेटिक तथा पोटेसिक उर्वरक नियंत्रण मुक्त थे। तथापि, इसलिए आयातित